जनवरी – फरवरी 2009

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

वर्ष : 32 अंक : 1

54 वॉ राष्ट्रीय अधिवेशन

Shri Narendra Modi Inaugurating 54th National Conference

National President Prof. Milind Marathe

Presenting Prof. Yashwantrao Kelkar Yuva Puraskar to Oinam Indira Devi

Releasing of the photo album of Anti Bangladeshi Infiltration Movement

Public Meeting

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 32 अंक : 1 ● जनवरी–फरवरी 2009

संरक्षक
अतुल कोठारी

संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhathrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

Cartoon Corner

विषय सूची

7 54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

9 राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

13 आध्यात्मिक भारत

15 ***Report of International Seminar on*** **'Global Terrorism'**

25 **Career**

26 **Right to Education More Rhetoric than Action**

मुलाकात

श्री विष्णुदत्त शर्मा – राष्ट्रीय महामंत्री अभाविप.....19

परिचर्चा

क्या प्रमाणित तौर पर स्लमडोग है भारत ??.....21

परिषद् गतिविधियां.....29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

National Office Bearers of ABVP

President	Prof. Milind Marathe	Thane	Maharashtra
Vice President	Dr.Payal Mago	Delhi	Delhi
	Dr.Reghuraj Kishore Tiwari	Rewa	Mahakoshal
	Dr.Kiran Hasarika	Debrugarh	Assam
	Dr.Rajaneesh Shukla	Varanasi	Eastern UP
	Shri M. Jayakumar	Trivandrum	Kerala
General Secretary	Shri Vishnudatt Sharma	Bhopal	Madhya Bharat
Secretary	Shri Samay Bansod	Nagpur	Vidarbh
	Shri Ravikumar	Bangalore	Karnataka
	Shri Umesh Dutt	Shimla	Himachal
	Shri Ramashankar Sinha	Mussafarpur	Bihar
	Kum.Aswini Paranjpe	Jabalpur	Mahakoshal
Organising Secretary	Shri Sunil Ambekar	Mumbai	Maharashtra
Joint Org.Secretary	Shri B.Surendran	Chennai	Tamilnadu
	Shri K.N.Reghunandan	Bangalore	Karnataka
Office Secretary	Shri Bharat Singh	Mumbai	Maharashtra
Treasurer	Shri Shyam Agrawal	Jaipur	Rajasthan

स्वात घाटी : भारत के लिए खतरे की घंटी

पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत स्थित स्वात घाटी इन दिनों सुर्खियों में है। तालिबान द्वारा इस पर किए गए कब्जे पर पाकिस्तान सरकार ने अपनी सहमति की मुहर लगाकर न केवल स्वात के लोगों को अमानवीय अत्याचार की आग में झोंक दिया है, बल्कि खुद पाकिस्तान के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खडे कर दिये हैं। बहरहाल स्वात में तालिबानीकरण की जो मुहिम छिड़ी है, उसका जितना दुष्प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा, भारत के लिए भी स्थिति उतनी ही चिंताजनक कही जा सकती है; क्योंकि यह तो विदित है कि पाकिस्तान में अब कानून एवं व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और देश को गर्त में धकेलने की जो कसर परवेज़ मुशर्रफ ने बाकी छोड़ी थी; तालिबान को अपनी जमीन पर आने का न्यौता देकर ज़रदारी सरकार ने उसे पूरा कर दिया है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण विषय सामने आते हैं, पहला तो स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता और उनके जीवन से जुड़ा है, जिस पर अब तालिबानियों का कड़ा पहरा लग चुका है। दूसरा विषय भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि स्वात में शरीयत कानून लागू कर देने तक ही इस कदम को नहीं देखा जाना चाहिए। माना यह जा रहा है कि स्वात में जीत का स्वाद चख लेने के बाद तालिबानी खामोश नहीं बैठेंगे। उनके हौंसले बुलंद होंगे तथा वे दोगुने उत्साह से अन्य इलाकों में अपनी जीत का परचम फहराने की कोशिश करेंगे। यह भारत के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि तालिबान का प्रभाव क्षेत्र बढ़ते–बढ़ते भारत की सीमा के काफी करीब आता जा रहा है।

हाल ही में तालिबान ने एफ.एम. पर लड़कियों को स्कूल भेजे जाने पर जान से मार देने की धमकी दी है और 100 से भी अधिक स्कूलों को धवस्त कर दिया गया। शरीयत के तमाम कानून अब वहां लागू हो गए हैं। विडंबना है कि मानवता के खिलाफ किए जा रहे इस अत्याचार पर मानवाधिकारवादियों ने भी मौन धारण कर लिया है। जबकि वही मानवाधिकारवादी भारत में नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे सुरक्षा बल के जवानों पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाकर रेड–कॉरीडोर से सुरक्षा बलों को हटा लेने की बात करने से नहीं चूकते। लेकिन स्वात के मामले में इन तथाकथित मानवाधिकारवादियों को भी सांप सूंघ गया है। तालिबानियों एवं अन्य आतंकी संगठनों का अगला निशाना पाकिस्तान के अन्य सूबे हो सकते हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर किए गए आतंकी हमले से इस गहराते संकट को समझा जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के खात्में को लेकर अमेरिका लम्बे समय से बमबारी कर रहा है। वहां हामिद करजई के नेतृत्व में सरकार जरूर कायम हो गई, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि तालिबानियों का आतंक भी अफगानिस्तान से खत्म हो गया है। आशय यह है कि अमेरिका की दादागीरी भी तालिबान के समक्ष फीकी पड़ने लगी है।

हम पहले ही नक्सलवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और देश की सीमाएं, चाहे वह बांग्लादेश हो, चीन से लगी सीमा हो या फिर पाकिस्तान से लगी सीमाएं, सभी राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनी हुई हैं। विडंबना है कि यूपीए सरकार भी देश की सीमाओं को लेकर कभी संजीदा नहीं रही। फिर अभाविप जैसे संगठनों ने देशव्यापी आंदोलनों की मदद से सरकार पर इस बारे में सोचने के लिए दबाव बनाया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सुरक्षा से जुड़े विषयों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ जनमानस में जागरूकता का प्रसार कर जनभागीदारी द्वारा सरकार पर इसके खिलाफ और भी कड़े कदम उठाए जाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। अभाविप ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नई चर्चा छेड़ने की पहल की है और सवाल खड़ा किया है कि यदि अमेरिका पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है तो भारत के लिए खतरा बन चुके पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? बात छिड़ी है तो दूर तक जरूर जाएगी, बशर्ते देश को नागरिकों, विशेषकर युवाओं को देश की सुरक्षा पर गहराते खतरों को ध्यान में रखकर अपनी भूमिका जरूर तय करनी होगी, जिससे सरकार पर पर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए दबाव बनाया जा सके। ■

ये हंगामा है क्यों बरपा...

– आशीष कुमार 'अंशु' –

आज से छह महीने पहले लोग जिस श्रीराम सेना को जानते भी नहीं थे, आज मीडिया की मेहरबानी से एक जाना पहचाना नाम बन गया है। जरा सोचिए श्रीराम सेना के दर्जन–दो दर्जन कार्यकर्ताओं ने अमनेसिया पब, मंगलौर (कर्नाटक) पर हमला करके अखबरों में जितनी खबर पाई और इलैक्ट्रानिक चैनलों की जितनी फूटेज खाई। इतना नाम कमाने के लिए 'विज्ञापन' कर उन्हें कितना खर्च करना पड़ता। पहली नजर में यही लगता है कि श्रीराम सेना वाले प्रमोद मुतालिक ने मीडिया को इस्तेमाल कर लिया। इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। जिसकी वजह से मीडिया की रूचि लंबे समय तक इस विशय में बनी रही। वह है मामले का हाई प्रोफाईल होना। यदि इस तरह का हमला किसी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में हुआ होता तो निश्चित मानिए मीडिया इतनी सक्रिय नहीं होती।

श्रीराम सेना ने जो किया उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता चूंकि उनका विरोध प्रद न का तरिका लोकतात्रिक नहीं था। लेकिन इस सबके बावजूद आप इस पूरे कथानक में जो 'नैनिकता के सवाल' उठे हैं, उसे कम करके नहीं देख सकते। जिस भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात की जा रही थी, वह श्रीराम सेना की अनैतिकता की वजह से दब सी गई। जबकि इस विशय में भी बात होनी ही चाहिए। क्या आप इसे ठीक मानेंगे कि इस बात की उपेक्षा सिर्फ इसलिए कर दी जाए क्योंकि श्रीराम सेना के कुछ उत्साहित नौजवानों ने गलत तरिके से इस विशय को उठाया है?

भले ही इस देश के दशमलव शून्य–शून्य–शून्य कुछ प्रतिशत लोग लाख उत्तर आधुनिकता का ढोल पीट लें, लेकिन आज भी भारतीय समाज में वह संस्कार कायम हैं, जिसे 'भारतीयता' कहते हैं। तमाम टीवी चैनलों पर लोग चिख–चिल्ला रहे थे, लेकिन हमले के बाद पीड़ित लड़कियां कहां गायब हो गई? कितने प्रतिशत अभिभावक देश में इस बात की इजाजत अपने लड़के–लड़कियों को देंगे कि वे पब में जाएं और भाराब–सिगरेट पीएं। रेव पार्टियों में अपने पुरूश मित्रों के साथ कोकिन, स्मैक और हेरोईन के साथ कृत्रिम बारिस का आनन्द उठाएं।

दर्जनों ऐसे मामले हैं, जब रातों–रात झुग्गी–बस्तियों को तोड़कर वहां रहने वालों को बेघर कर दिया गया। यह मामला श्रीराम सेना के कर्म से कहीं बढ़कर भयावह और भार्मनाक है। लेकिन किसी चैनल वाले की आंख न खुलती। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलन्द करने का द ा करने वाली मीडिया ना जाने उस वक्त कहां सो जाती । वजह साफ है कि चूंकि वहां मामले 'लो प्रोफाइल' होते । इसलिए दब जाते हैं। खबरिया चैनलों का उद्दे य ख देना बिल्कुल नहीं है। उनका उद्दे य है, द किों मनोरंजन करना और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर अब श्रीराम सेना वाली खबर में मामला हाई प्रोफाइल है मामले से सबंधित विजुअल्स चैनल वालों के पास हैं, इस खबर के साथ में ड्रामा है और मनोरंजन भी भरपूर और क्या चाहिए 'खबर' के लिए? साप्ताहिक पत्रि आउटलुक (अंग्रेजी) ने अपना 9 फरवरी 2009 के अंक श्रीराम सेना के कारनामे को समर्पित किया है। इसी अंक के पृश्ठ 37 पर पीड़ित लड़कियों की तस्वीर प्रका ीत की गई है। लेकिन इस तस्वीर में पीड़ितों के चेहरे को ढंक दिया गया है, आखिर ऐसा क्यों?

यदि पब में जाना बच्चों की आजादी से जुड़ा मस है, तो उनकी आजादी की रक्षा के लिए उन बच्चों के मां–बाप को सामने आकर कहना चाहिए था– 'हमारे बच्चे यदि पब–बीयर बार– नाइट क्लब में जाते हैं तो किसी को क्यों आपत्ती है?' अब सोचने वाली बात यह कि कौन है जो इस खबर को हवा दे रहा है। वही जो इस दे ा में पब–नाइट क्लब–बीयर बार की पि चमी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं। जिसने भारत जैसे दे ा में 'वेलेन्टाइन' का इतना बड़ा बाजार खड़ा कर दिया। आज कोई इसके विरोध में बोले तो उसे 'आउट डेटेड' ही समझा जाएगा। अच्छी बात यह है कि बाजार के तमाम हथकंडों के बाद भी भारतीय आम समाज के बीच ना वेलेन्टाइन कल्चर को स्वीकृति मिली है ना ही नाइट क्लब कल्चर को। बहरहाल मीडिया ने जिस हल्केपन के साथ इस संवेदन ाील मामले को जनता के सामने रखा है, उससे पूरी बात स्पश्ट होकर सामने नहीं आई है। वहां से इक तरफा बात की गई है, जिसकी वजह से दूसरा भारतीय पक्ष लगभग अनसुना रह गया। ■

54 वॉ राष्ट्रीय अधिवेशन

दिनांक 23 से 26 जनवरी 2009
जलगाँव (महाराष्ट्र)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 54 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 23 जनवरी को दीप प्रज्जवलन कर किया। युवाओं में आत्मविश्वास की चिंगारी फूंकते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि परिश्रम से स्थिति को बदला जा सकता है इसके लिए मन में निराशा के भाव को मारना होगा । श्री मोदी ने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि आम आदमी को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी । साथ ही स्वयं एवं देश को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा ।

54 वॉं राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर महाराष्ट्र के प्रमुख शिक्षा केन्द्र एवं स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जलगाँव शहर (महाराष्ट्र) में दिनांक 23 से 26 जनवरी 2009 को सम्पन्न हुआ । राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जन्मशताब्दी वर्ष के निमित्त अधिवेशन परिसर को 'तुकडोजी महाराज नगर' नाम दिया गया था । मुम्बई में हुई आतंकी हमले के शहीदों की स्मृति में मुख्य सभागार का नाम 'शहीद सभागृह' रखा गया था । 54 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व निर्धारित अपेक्षित सूची में से 460 स्थानों से कुल 1006 प्रतिनिधि सहभागी हुए। जिनमें 794 छात्र, 113 छात्राएँ, 82 अध्यापक तथा 17 अन्य कार्यकर्ता समाहित हैं ।

तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 रामनरेश सिंह एवं महामंत्री श्री सुरेश भट्ट ने दिनांक 23 जनवरी, 09 को दोपहर सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए अधिवेशन का शुभारंभ किया।

विद्यार्थी परिषद् के वर्ष 2007–08 की गतिविधियों अर्थात कानपुर राष्ट्रीय अधिवेशन से जलगाँव राष्ट्रीय अधिवेशन तक का महामंत्री प्रतिवेदन श्री सुरेश भट्ट (राष्ट्रीय महामंत्री) द्वारा सभी प्रतिनिधियों के सम्मुख रखा गया । राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2007–08 की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् के कार्यकाल समाप्ति की घोषणा के पश्चात निर्वाचन अधिकारी डॉ. दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (अजमेर) ने चुनाव प्रक्रिया का जानकारी देते हुए वर्ष 2008–09 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हेतु प्रो. मिलिंद मराठे (ठाणे, महराष्ट्र) तथा राष्ट्रीय महामंत्री हेतु श्री विष्णुदत्त शर्मा (भोपाल, मध्य भारत) को सर्वानुमति से निर्वाचित घोषित किया । दोनों पदाधिकारियों ने अपने पद ग्रहण करते हुए मनोगत व्यक्त किया ।

कार्यक्रम में बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आन्दोलन की 'फोटो पुस्तिका' का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे द्वारा किया गया ।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष–महामंत्री, महारष्ट्र के प्रांत अध्यक्ष – मंत्री तथा स्वागत समिति अध्यक्ष – सचिव उपस्थित थे।

राष्ट्रीय अधिवेशन में निम्न विषयों पर भाषण हुए

1) बदलता परिसर परिदृश्य व हमारे कार्य की दिशा : श्री के. एन. रघुनंदन (क्षेत्रीय संगठन मंत्री, दक्षिण – पश्चिम एवं दक्षिण–पूर्व भारत)

2) राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ एवं हमारी भूमिका – श्री सुनील बंसल (क्षेत्रीय संगठन मंत्री,उत्तर–पश्चिम क्षेत्र)

शिक्षा के व्याप्त भ्रष्टाचार, व्यवसायीकरण, विश्वविद्यालयों में बढ़ता आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ तथा देश में आर्थिक क्षेत्र के घोटाले

आदि विषयों पर राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए ।

1) केन्द्र सरकार की अनर्थकारी शिक्षा नीति ।

2) सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा।

3) आर्थिक जगत के घोटाले – उदारीकरण की देन ।

वर्ष 2008 में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के जिन गणमान्य व्यक्तियों का निधन हुआ, उनके प्रति शोक प्रस्ताव भी प्रारित किया गया ।

प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार : 54 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए एक विशेष कार्यक्रम में दिनांक 25 जनवरी को वर्ष 2008 का प्रो.यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्रदान किया गया । मणिपुर की सुश्री ओईनम इंदिरा देवी को महिलाओं एवं बच्चों के लिए गरीबी निर्मुलन, संपूर्ण देखभाल तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया । प्रो.यशवंतराव केलकर के प्रेरणादायी प्रसंगों के द्वारा उनका जीवन कथन श्री विष्णुदास (क्षेत्रीय संगठन मंत्री, पूर्व क्षेत्र) ने किया। राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने अभाविप व विद्यार्थी निधि द्वारा संयुक्त रूप से संचालित युवा पुरस्कार की घोषणा की । पद्मश्री भंवरलाल जैन द्वारा सुश्री ओईनम इंदिरा देवी को पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं राशि प्रदान की गयी । दिनांक 22 जनवरी को अधिवेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन एडवोकेट अच्युतराव अत्रे ने किया । प्रदर्शनी में विद्यार्थी परिषद् की विभिन्न प्रांतों की गतिविधियाँ, बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आन्दोलन आदि विषय प्रदर्शित किये गए । कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. किरण हजारिका का भाषण भी हुआ। दिनांक 24 जनवरी को शोभायात्रा का आयोजन हुआ । अधिवेशन में आये सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों ने शोभायात्रा में हिस्सा लेते हुए, उद्घोष लगाते हुए अपनी एकता और शक्ति का परिचय दिया । शोभायात्रा के पश्चात हुए खुले अधिवेशन को श्री विष्णुदत्त शर्मा (राष्ट्रीय महामंत्री), श्री समय बनसोड (राष्ट्रीय मंत्री), श्री संदीप कुमार (राष्ट्रीय मंत्री), श्री श्रीनिवास (राष्ट्रीय मंत्री), श्री प्रकाश बेलवाडे (प्रांत मंत्री, महाराष्ट्र), सुश्री सुस्मिता दास (उड़ीसा), श्री अमोल पाटील (जलगाँव) आदि छात्र नेताओं ने सम्बोधित किया । शोभायात्रा में लगभग 3200 स्थानीय छात्र–छात्राओं ने भी हिस्सा लिया।

खुला अधिवेशन के पश्चात दिनांक 24 जनवरी रात्रि को अधिवेशन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गोंधल, लावणी, पावरा आदि ने सभी प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध किया।

अधिवेशन स्थल पर 3 प्रांतों के प्रांत अधिवेशन सम्पन्न हुए जिनमें बिहार, विदर्भ एवं मध्य उत्तर प्रदेश शामिल है । राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2008–09 की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की घोषणा की गई । जिसमें सभी प्रांतों के प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री तथा मुंबई के अध्यक्ष, मंत्री एवं अन्तर्राज्य छात्र जीवन दर्शन (SEIL) के अध्यक्ष, महामंत्री से अपेक्षित रहेंगे ।

अधिवेशन की व्यवस्था सह प्रमुख श्री लिमजी जलगाँववाला ने व्यवस्था एवं उसमें लगे सभी प्रबंधन कार्यकर्ताओं का संक्षिप्त परिचय कराया, जिनका अधिवेशन में आये सभी प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि से अभिनंदन किया। अधिवेशन के व्यवस्था प्रमुख डॉ. रविन्द्र कुलकर्णी भी उपस्थित थे । अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने 54वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समारोप भाषण किया । उन्होंने कहा कि 'हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारा ध्येय इतना सटीक और मजबूत है, उसमें इतनी ताकत है कि एक पीढ़ी नहीं लगातार आने वाली कई पीढ़ियों के नौजवानों को एक सतत रूप से प्रेरणा देता जा रहा है कि ये देश मेरा है मुझे इस देश के लिए कुछ करना है । समारोप भाषण के पश्चात वंदे मातरम तथा ध्वजावतरण के साथ 54वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ । ■

राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव – 1

केन्द्र सरकार की अनर्थकारी शिक्षा नीति

वर्तमान में देश का शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा में व्यवसायीकरण, विश्वविद्यालयों में बढ़ता भ्रष्टाचार एवं कुलाधिपतियों द्वारा कुलपति जैसे पवित्र स्थानों पर भ्रष्ट एवं अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ, सरकार द्वारा शिक्षा को सेझ (SEZ) की परिधि में लाकर शिक्षा का पूर्णतया बाजारीकरण करने का प्रयास जैसी भयावह समस्या से जूझ रहा है ।

देश के कुछ प्रांतों में हाल ही में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में हो रही राजनीतिक दखलंदाजी एवं बडे पैमाने पर होने वाले धन के लेनदेन की घटनायें शर्मनाक हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे दोनों बड़े राज्यों में 6–6 कुलपतियों को भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाये जाने की घटनायें शिक्षा के क्षेत्र में निंदनीय एवं सोचनीय है । इस कारण से कुलपतियों की नियुक्ति करने वाले कुलाधिपति की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है, केवल इतना ही नही अपितु कई प्रांतों में तो कुलाधिपति कार्यालय ही राजनीति एवं भ्रष्टाचार के सबसे बडे अड्डे बनकर उभरे हैं। अभाविप का 54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन इसकी कड़ी निंदा करता है और यह माँग करता है कि देशभर के कुलपतियों के नियुक्ति के स्पष्ट मापदंड तय हों ।

अभाविप द्वारा किये गये अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के देशव्यापी सर्वेक्षण तथा उसके बाद चलाये गये प्रभावी आंदोलन से कई प्रांतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवासों की स्थिति में सुधार होना प्रारंभ तो हुआ है किंतु लगातार संघर्ष के बाद भी सरकार के उदासीन रवैये के कारण विद्यार्थी परिषद् ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया तथा केन्द्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से सपष्टीकरण माँगा है ।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के समकक्ष दर्जा दिये जाने की सिफारिशों को स्वीकार करना व मदरसों को गुणवत्ता संवर्धन (SQPM) योजना के नाम पर आर्थिक मदद पहुँचाने तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दूसरे राज्यों में परिसर खोलने के लिए 2,000 करोड़ रूपयों के अनुदान का प्रावधान करने जैसे कदम उठाये गये हैं ऐसे कदम केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह के अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के षड़यंत्र को एक बार फिर उजागर करते हैं जो देश की शिक्षा के लिये गंभीर चिंता का विषय है । अभाविप 54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ऐसे निर्णयों को रद्द करने की माँग करता है ।

भारत कृषि प्रधान देश है फिर भी देश में कृषि और पशु चिकित्सा शिक्षा की स्थिति अत्यंत सोचनीय बनी हुई है। कृषि शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या, उनकी मूलभूत व्यवस्थाएं, स्थानीय आवश्यकता से दूर भागते पाठ्यक्रम आदि विषयों के बारे में कृषि शिक्षा की गंभीर अवस्था ध्यान में आती है । कृषि शिक्षा में प्रांतों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित न हो पाने से उसकी उपयोगिता न के बराबर है । अभाविप का 54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन सरकार से यह माँग करता है कि कृषि वानिकी एवं पशुचिकित्सा शिक्षा के लिये देशभर में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो की संख्या बढ़ानी चाहिये और विद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिये तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाकर देशभर में कृषि शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में पहल करनी चाहिये । साथ ही Rural agricultural working experience, Agricultural Polytechnic, Agro Clinic, जैविक कृषि (Organic Farming) जैसे प्रयोग शुरू किये जायें एवं कृषि विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध को किसानों तक पहुँचाने का प्रभावी तंत्र बनाने से भी केन्द्र व राज्य सरकार पहल करें ।

देश में कृषि शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिये अत्याधुनिक तकनीक के साथ स्वदेशी एवं परम्परागत कृषि तकनीक के विकास की भी आवश्यकता है क्योंकि देश की अधिकांश कृषि स्वदेशी एवं परंपरागत तकनीक के आधार पर ही कार्य कर रही है लेकिन दुर्भाग्य से कृषि शिक्षा में स्वदेशी एवं परंपरागत तकनीक के विकास की अवहेलना हो रही है जो भारतीय कृषि के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

अभाविप के 54 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का मानना है कि देश में जिस प्रकार से बाजार की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों की माँग उठी है जिसके चलते स्ववित्त पोषित के नाम पर निजी संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम बड़े भारी शुल्क के साथ आए दिन खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये शुल्क निर्धन छात्रों के पहुँच से बहुत दूर है। सरकारी संस्थाऐं तथा विश्वविद्यालय भी उनका अनुसरण करके शिक्षा के व्यवसायीकरण की पराकाष्ठा पर रही है । परिसर चयन (Campus Selection) व रोजगार आश्वासन (Job Guarantee) के नाम पर छात्रों से लिए जा रहे शुल्क पर रोक लगे तथा रोजगार नहीं मिलने पर शुल्क वापसी की व्यवस्था हो, साथ ही प्रदेश में इसकी नियंत्रित करने की व्यवस्था बनाई जाये ।

देश में कई प्रांतों में मानिक विश्वविद्यालय (Deemed University) की मूल संकल्पना अब बदलती हुई नजर आ रही है । शैक्षिक उत्कृष्टता (Academic Excellence) का मूल उद्देश्य अब पीछे छोड़कर केवल पैसा कमाने का उद्देश्य हावी हो रहा है । राज्य सरकारों के दायरे से मुक्त होना, शुल्क निर्धारण समिति के परिधि से बाहर आना, परिसर विहिन केन्द्र (Off Campus Centres) खोलना और विदेशी विश्वविद्यालयों से गठजोड़ बिठाना इत्यादि निहीत स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए मानित विश्वविद्यालय बनने की होड लगी है । इससे न केवल मानित विश्वविद्यालय की मूलभूत कल्पना को धक्का लगा है अपितु शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा ही मिला है जिसके प्रति अभाविप का 54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन चिंता व्यक्त करता है ।

केन्द्र सरकासर ने एक आदेश जारी कर दंत चिकित्सा (B.D.S.) पाठयक्रम के कार्यानुभव (Internship) को खत्म करते हुए पाँच वर्ष कर दिया है । इस कदम से विद्यार्थी प्रायोगिक कार्य का अनुभव व छात्रवृत्ति से विमुख हो गये हैं । अभाविप इस निर्णय का विरोध करती है तथा यह मांग करती है कि सरकार निजी संस्थाओं के दबाव से मुक्त होकर छात्रों के कार्यानुभव (internship) व छात्रवृत्ति को यथावत जारी रखे।

अभाविप केन्द्र सरकार के शिक्षा के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) की परिधि में लाकर शिक्षा के बाजारीकरण करने के प्रयास का पहले से ही विरोध करती आयी है । किंतु सरकारें अपने मनमानेपन से बाज आती नहीं दिखाई पड़ रही हैं । अभाविप का 54 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन यह माँग करता है कि सरकार शिक्षा के व्यवसायीकरण पर तुरन्त रोक लगाये अन्यथा आने वाले समय में समूचे देश में छात्रों के अत्यन्त तीव्र आंदोलन का सामना करने के लिये तैयार रहे । साथ ही देश के सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह करती है कि वे लोकसभा चुनाव से पूर्व शिक्षा के बारे में अपने देश की कार्यनीति निश्चित करके उसे घोषणा पत्र के माध्यम से उजागर करें । ■

प्रस्ताव – 2

सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा

26 नवम्बर को मुम्बई में हुए आतंकी हमलें और पूर्व के बम विस्फोटों के कारण भारत की जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी प्रशिक्षण केन्द्रों और भारत में उनके सहयोगी लोगों पर सीधी कार्यवाही करनी चाहिये। गत वर्षों से देशभर में हो रहे आतंकी हमलों से त्रस्त जनता के आक्रोश को तुष्टीकरण के दलदल में आकंठ डूबी यूपीए सरकार ने अनदेखा कर दिया । अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आतंकी हमलों के शहीदों और मारे गये निर्दोष लोगों को श्रद्धांजली अर्पित करता है । साथ ही आतंकी हमलों का सीधा प्रसारण दिखाने के बारे में सरकार एवं मीडिया को कुछ नीति बनाने की आवश्यकता भी दिखाई देती है तथा मीडिया से आग्रह करती है कि वो इस प्रकार की घटनाओ के प्रसारण में सतर्कता बरते । विद्यार्थी परिषद मुस्लिम समाज द्वारा हमलावरों के शवों को कब्रिस्तान में जगह न देने की राष्ट्रवादी सोच की पहल का स्वागत करता है।

अभाविप का मानना है कि आतकी हमले को केवल मुम्बई पर हमला न मानकर भारत पर आक्रमण मानते हुए केन्द्र सरकार को इसका जवाब युद्ध भाषा में देते हुए पाकिस्तान पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिये थी । यह जग जाहिर है कि मुम्बई हमलों व भारत में आतंकवाद को पोषित करने का काम पाकिस्तान प्रेरित है। परन्तु यह भी सत्य है

कि बार–बार हो रहे हमले केन्द्र सरकार की सुरक्षा के प्रति लापरवाही को भी प्रकट करते हैं । अत: सरकार तुरन्त सुरक्षा एजेन्सियों व खुफिया तंत्र की खामियों को ठीक कर आतंकी हमलों को रोकने की रणनीति बनाये ।

अभाविप का सुविचारित मत है कि आतंकवाद से लड़ने में केन्द्र सरकार ने लीपापोती कर देश की जनता को भ्रम में रखा है। भारत सरकार पश्चिमी देशों के भरोसे आतंकवाद से लड़ना चाहती है परंतु आतंकवाद के मुद्दे पर इन पश्चिमी देशों का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। आतंक [redacted] पाक के खिलाफ यह लड़ाई भारत की है और इसे भारत को ही लड़ना पड़ेगा और इसकी पहल पाकिस्तान पर दबाव के साथ–साथ देश भर में पनप रहे आतंक के ठिकानों व छुपे दल पर समान्तर कार्यवाही करनी चाहिये । साथ ही केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक तष्टीकरण व वोट बैंक की राजनीति से बाहर आकर अफजल गुरू को फांसी दे एवं बाटला हाऊस तथा मुम्बई हमलों के शहीदों का अपमान करने वाले केन्द्रीय मंत्री अर्जुन सिंह व अंतुले, जामिया विश्वविद्यालय कुलपति मशरूल हसन पर कठोर कार्यवाही करे । विद्यार्थी परिषद् का मानना है कि बांग्लादेश से हो रही निरंतर घुसपैठ के कारण पूर्वोत्तर भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश आज असुरक्षित हो गया है। ढीले–ढाले सीमा प्रबंधन वं वोट बैंक राजनीति के कारण करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिये भारत में फैल गये हैं । जिनके कारण जनसंख्या संतुलन बिगड़ना, अवैध हथियार, मादक पदार्थ व जाली नोटों व पशु तस्करी होना व आतंकी संगठनों को आतंकी उपलब्ध हो रहे हैं । इन घुसपैठियों के कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं।विद्यार्थी परिषद द्वारा गत वर्षों से चलाये गये घुसपैठ विरोधी आंदोलन का ही परिणाम है कि भारत के गृहमंत्री श्री पी.चिदम्बरम द्वारा घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा मानते हुए कार्यवाही करने के संकेत दिया गया जो स्वागत योग्य है, परंतु घुसपैठ के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

देश की आन्तरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे नक्सलवादियों से निपटने में भी केन्द्र सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है । वामपंथी विचारों से प्रेरित ये नक्सली कई राज्यों के कुछ जिलों में समानान्तरण प्रशासन चला रहे हैं, नक्सलीयों द्वारा हजारों निर्दोष लोगों का खून बहाने के बावजूद केन्द्र सरकार किंकर्तव्यमूढ़ की स्थिति में है । वही दूसरी और छत्तीसगढ़ में नक्सलीयों के खिलाफ चले शांति अभियान 'सलवाजुड़म' में आम जनता का सहयोग अभिनन्दनीय है तथा परिषद् इस आन्दोलन का समर्थन करती है । विद्यार्थी परिषद् सरकार से मांग करती है कि नक्सली हिंसा से निपटने के लिये प्रभावित राज्यों से तालमेल करते हुए केन्द्रीय स्तर पर कार्यवाही कर क्योंकि यह विषय राज्यों के साथ – साथ देश व आम व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा है ।

उड़ीसा के कंधमाल में 27 अगस्त को स्वामी लक्ष्मणानंद की चर्च एवं नक्सल प्रेरित आतंकी द्वारा हत्या किये जाने की विद्यार्थी परिषद निंदा करती है साथ ही इनकी हत्या की न्यायिक जांच और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करती है । अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देश की सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न इन गंभीर खतरों को देखते हुए केन्द्र सरकार से मांग करता है कि मात्र कानून बनाने व एजेन्सी गठित करने तक सीमित न होकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े व पाकिस्तान को भी सबक सिखाये। साथ ही यह अधिवेशन देश की जनता से भी आह्वान करता है कि मुम्बई हमलों के बाद जो जनाक्रोश देश की सड़कों पर देखने को मिला उसको कमजोर न पड़ने दें जिससे केन्द्र सरकार पर दबाव कायम रह सके ।

यह अधिवेशन सरकार से स्पष्ट माँग करता है कि :–

- पाकिस्तान को आतंकी एवं बांग्लादेश को शत्रु देश घोषित किया जाये।
- पाक अधिकृत कश्मीर (POK) व बांग्लादेश स्थित आतंकी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आक्रमण करके ध्वस्त करे ।
- सीमा क्षेत्र के प्रबंधन की व्यवस्था ठीक कर सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाये ।
- केन्द्र सरकार द्वारा घुसपैठ पर ठोस रणनीति बनाकर घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने के लिए गंभीर प्रयास किये जायें । ■

प्रस्ताव – 3

आर्थिक जगत के घोटाले – उदारीकरण की देन

पाश्चात्य अर्थनीति के अन्धानुकरण के कारण आई वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर ने आर्थिक क्षेत्र व उद्योग जगत में भी उथल पुथल उत्पन्न की है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पाश्चात्य अर्थनीति को अपनाने के कारण बड़े–बड़े घोटाले हुए, जिन्होंने भारतीय अर्थतंत्र को प्रभावित

किया । जिसकी विद्यार्थी परिषद् कड़े शब्दों में निन्दा करती है। आर्थिक मंदी के इस दौर में जिस प्रकार से रोजगार के अवसर घट रहे है, बड़े–बड़े उद्योगों की सतत छंटनी हो रही है, उससे छात्र विशेषकर जो आई.टी., इंजीनियरिंग, एमबीए आदि क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है उनमें हताशा व्याप्त है । यद्यपि कथित विश्वव्यापी आर्थिक मंदी (Economic Melt Down) के कारण ऐसी कम्पनियों के घोटाले सामने आने लगे हैं, जिन्होंने बाजार में अपनी कृत्रिम मांग बना रखी है। इस आर्थिक मंदी के चलते पाश्चात्य जगत के कई देश दिवालियों की स्थिति में हैं, रोजगार के अवसर घट रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में यह मंदी पर्याप्त सीमा तक निष्प्रभावी रही है । क्योंकि उदारीकरण के दौर में भारत ने थोड़ा देर से प्रवेश किया है। साथ ही देश में अर्थव्यवस्था स्थायी सामाजिक आधार पर निर्भर है, जो मूल उत्पादकता से जुड़ी है ।

उदारीकरण के प्रभाव के चलते ही सत्यम के अध्यक्ष बी. रामालिंगाराजू द्वारा की गई वर्षों से लाभ दर में दिखाई गई झूठी बढ़ोतरी का भाँड़ाफोड़ होने से भारतीय उद्योग जगत विशेषतः सूचना तकनीकी क्षेत्र को गहरा धक्का पहुँचा है, इस क्षेत्र में भी दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड में किसी भी तरह का नियंत्रण न होने के कारण से विगत कई वर्षों से जनता की आंखों में धूल झोंक कर सत्यम कम्पनी के अध्यक्ष निर्देशक मण्डल के सदस्यां व इससे जुड़ी ऑडिट कंपनी ने जो धोखाधड़ी की है अभाविप उसकी घोर निंदा करती है ।

श्री रामालिंगाराजू द्वारा सत्यम का लाभ, 13000 कर्मचारियों को बिना नियुक्ति पत्र दिये उनके खातों में वेतन भी हस्तांतरित कर अपने परिवार के लोगों को पहुँचाया गया। तथा हैदराबाद व देश के प्रमुख स्थानों पर बेशकीमती जमीन खरीदी गई जो इस घोटाले की एक कड़ी है। सत्यम घोटाले में संलिप्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कम्पनी, बैंकर, SEBI के अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए । इसके साथ सत्यम के अध्यक्ष के राजनैतिक आकाओं से सम्बन्धों की जाँच करवाई जाए जिसके चलते उनके परिवार की कम्पनी मेटास केवल 4 वर्षों में 30,000 करोड़ तक पहुँच गई तथा हैदराबाद व आसपास अरबों की भूमि खरीद की गई । विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि बी. रामलींगाराजू के परिवार द्वारा स्थापित देशभर में 40 कम्पनियों की जाँच हो तथा उनकी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर निवेशकों के भविष्य व पूँजी की रक्षा हो तथा इस पूरे घोटाले की C.B.I से जाँच करवाई जाएं जिससे वास्तविकता देश के सामने आ सके ।

परिषद् का मानना है कि भविष्य में ऐसी घटनां न हों इसके लिए –

- औद्योगिक संस्था अधिनियम 1956 में आवश्यक बदलाव किए जाऐं ।
- निदेशक मंडल (Board of Director) की बैठक में होने वाले निर्णयों को सूचना का अधिकार (RTI) की परिधि में लाया जाए।
- अंकेक्षण संस्था जो इस तरह के घोटालों में सहयोगी बनती है उन पर कड़ी कार्यवाही व भविष्य में निरीक्षण अंकेक्षण कार्य को अयोग्य घोषित किया जाए।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की भूमिका को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया जाए ।
- बड़े औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर संगठनों के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन हो ।
- घोटालों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाए ।

विद्यार्थी परिषद् केन्द्र की UPA सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश हेतु 26% से 49% तक खोलना तथा अब और उदारता दिखाते हुए इस प्रतिशत को और बढ़ाने हेतु बिल लाकर विदेशी बीमा क्षेत्र की कम्पनियों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है । विद्यार्थी परिषद इसकी निन्दा करती है ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के नाम पर देश भर में केवल लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऐसे प्रतिष्ठानों की स्थापना की जा रही है जो केवल कुछ लोगों को ही लाभ पहुँचायेंगे। अपने कानून व नियमों वाले ऐस SEZ पर सरकार भविष्य में क्या नियंत्रण कर पायेगी इस पर परिषद संदेह व्यक्त करती है तथा इस विषय पर पुनर्विचार की माँग करती है ।

विद्यार्थी परिषद का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थचिन्तन के आधार पर होनी चाहिए । देश की आवश्यकता के अनुसार ही उदारीकरण को अपनाया जाना चाहिए । इसकी आवश्यकता को आज उदारीकरण के पक्षधर भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने भी मजबूरी में इसे स्वीकार किया है। अभाविप सरकार से मांग करती है कि देश के व्यापक हित में भारतीय अर्थनीति पर राष्ट्रीय बहस करते हुए देश की आवश्यकता के अनुरूप भारतीय अर्थ विचार को ध्यान में रखते हुए व्यापक बदलाव लाएं । ■

आध्यात्मिक भारत

– आशुतोष भटनागर –

ब्रह्म के 'एकोहं बहुस्याम्' संकल्प से अदभुत् सृष्टि का प्राकट्य जहां हुआ, मानव जीवन ने सर्वप्रथम जहां अपनी आंखें खोली, जहां सृष्टि और सृष्टा के संबंध का चिंतन हुआ, मानव मात्र के कल्याण के स्वर जहां गूंजे, समुत्कर्ष और निश्रेयस्, दोनों का सम्यक् विचार और तदनुकूल आचार पद्धति का विकास हुआ, शश्वत जीवन मूल्य जहां समाज जीवन का अंग बने, वह 'भारत' अपने चिरंतन ज्ञान, दर्शन और संस्कृति के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जहां से चेतना और ऊर्जा प्राप्त करता है, उसका मूलाधार अध्यात्म है। भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और अपनी इस विशिष्टता के लिये ही युगों–युगों से विश्व में पूजित हुआ है।

भारतीय तत्वचिंतन का उदगाता ऋषि अपनी अनभूति को अपने तक सीमित नहीं रखता, लोक कल्याण के लिये ऋचाओं की रचना कर समाज को सौंप देता है। वह अपनी ही नहीं, सबकी मुक्ति की कामना करता है। इस हेतु ज्ञान राशि के इस विपुल भंडार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिये वाचिक परम्परा भी सृजित करता है।

अपने इस कृतित्व के लिये ऋषि नितांत अनामिक भाव से वेद, पुराण, उपनिषद, काव्य इतिहास, निरुक्त सभी को उस 'कविर्मनीषी परिभूस्वयंभू' की ही रचना, उसका उच्छवास बताता है। यह ऋषि किसी दूत या पैगम्बर की तरह किसी अदृश्य शक्ति का प्रकट माध्यम भर नहीं है । उसने तप और साधना के बल पर अपने ही भीतर विद्यमान अंतर्यामी का साक्षात्कार किया है और उसकी ही वाणी को शब्द दिये हैं।

ऋषियों के चिन्तन से प्रसूत भारत का यह अध्यात्म मनुष्य के दैनंदिन जीवन से परे ईश्वरीय आदेश से किया जाने वाला कोई कर्मकाण्ड नहीं है। यह मानव जीवन में अंतर्निहित है। यह जीवन के साथ –साथ चलता है। ईश्वर द्वारा किसी दूत के माध्यम से बताये गये कर्तव्यों का निर्वहन या आदेश पालन इसका उद्देश्य नहीं है। इसका लक्ष्य तो ईश्वर की ओर आगे बढ़ना, ईश्वर को पाना, अंततः स्वयं ईश्वर हो जाना है। यह नर से नारायण की यात्रा है।

स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने धर्म की पश्चिम प्रदत्त व्याख्या के आलोक में भारत भूमि से उपजी धर्म की शाश्वत अवधारणा को समझने की कोशिश की । वे यह अनुभूति पाने में विफल रहे कि सनातन धर्म की शाश्वत अवधारणा में स्व के साक्षात्कार हेतु विकसित सभी आध्यात्मिक साधना पद्धतियां समाहित हैं जिन्हें इस भूमि पर सब प्रकार से फलने–फूलने के अवसर स्वतः ही प्राप्त हैं। यही इस राष्ट्र की अनेकता में एकता की विशिष्ट जीवन शैली है।

अनुचित रूप से इसकी तुलना एकपंथीय अब्राहमिक सम्प्रदायों से करने के कारण उन्होंने शासन विधान में एक विजातीय तत्व धर्मनिरपेक्षता को प्रतिष्ठित किया। संवैधानिक संरक्षण में इसे सार्वजनिक जीवन में पोषित ओर प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम के राजनैतिक दर्शन से प्रेरित राष्ट्रीय नेतृत्व ने धर्म को अंग्रेजी के 'रिलीजन' शब्द का पर्यायवाची माना तथा राजनीति के मार्गदर्शक तत्वों से उसे वहिष्कृत कर दिया । 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया।

पश्चिम की दृष्टि में समग्र जीवन पद्धति ही संस्कृति है जो रहन–सहन, खान–पान, साहित्य, संगीत, कला, शिल्प,

बारह सौ वर्षों के सतत संघर्ष से थक कर सोये भारत को एक बार पुनः जगाने की आवश्यकता है। अध्यात्म की आध ारशिला पर खड़ा यह राष्ट्र आज भी अविचल है, अजेय है। इस धरती को अपनी मां मानने वाले प्रत्येक भारतीय की आत्मिक शक्ति और अदम्य ऊर्जा को सूत्रबद्ध और संगठित कर सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के जागरण के उद्घोष की प्रतीक्षा विश्व कर रहा है।

सामाजिक व्यवस्था और नियम–कानूनों का योग है। धर्म उसका एक छोटा अंश है, जोकि आधुनिक परिभाषा में नितांत व्यक्तिगत है। राज्य और समाज के संचालन में उसकी कोई भूमिका नही है। इसलिये संस्कृति के इस समग्र रूप में से धर्म तत्व निकाल दिया जाय तो भी बहुत कुछ बच रहता है। इसलिये वहां धर्मनिरपेक्षता संभव है, राज्य अथवा समाज की नीति के रूप में स्वीकार्य है। पश्चिम की इस अवधारणा के विपरीत भारत में संस्कृति, साहित्य, शिल्प, जीवन पद्धति, आचार–व्यवहार, लोक जीवन, तीर्थाटन, न्याय, राजनीति, समाज व्यवस्था आदि सभी का अंतर्भूत तत्व धर्म है। धर्म को निरस्त करने का अर्थ है उक्त सभी को निरस्त करना। अपनी ही आत्मसत्ता को नकारना।

भारत में जो धर्म के विरुद्ध है वह संस्कृति का अंग कदापि नहीं हो सकता। अर्थ, काम और मोक्ष की साधना भी धर्म के अनुसार ही किये जाने की व्यवस्था है। धर्म से निरपेक्ष होने का अर्थ है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परम्परा और अपनी अस्मिता से निरपेक्ष हो जाना, जो किसी भी जीवंत समाज के लिये अस्वीकार्य है, असंभव है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की व्यवस्था वैदिक काल से हमारे ऋषियों–मुनियों ने हमें दी है, उसमें जीवन के सर्वांगीण विकास का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को ही स्वीकार किया गया है। इस मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही भारत में विविध मत–पंथों के बीच अध्यात्म के रूप में सर्वस्वीकार हुआ ।

वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में अध्यात्म को स्थापित करने के लिये ही धर्म की सृष्टि हुई। धर्म हमारे जीवन की नींव है और इस धर्म के परिपालन के कारण देश में जो लोक व्यवहार प्रचलित हुआ उसी से हमारी वैदिक सनातन संस्कृति प्रकट हुई। वैदिक परम्परा में कहा गया है– 'यतो अभ्युदयनिःश्रेयससंसिद्धि सः धर्मः' । 'धर्म' अर्थात जिसे आचरण में उतारा जा सके – 'धारयते इति धर्मः'। धर्म की यह अवधारणा भारतीय समाज में जीवन के अंतर्निहित तत्व के रूप में सहस्त्रों वर्षों से प्रवाहमान है ।

विश्व के मानचित्र पर अनेकों देश हैं जिनकी अपनी–अपनी विशिष्टताएं है। इस मालिका में मणि के रूप में प्रतिष्ठित भारत की विशेषता तो यहां की आध्यात्मिक जीवनशैली ही रही है। यहां की शिक्षा, सभ्यता, गौरव, बल और महत्व का मूल इसकी आध्यात्मिक शक्ति ही है। आत्मचिंतन, ध्यान, प्राणायम, प्रार्थना, जप, तंत्र–मंत्र, विविध यौगिक क्रियाएं, यज्ञ–हवन, भक्ति, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञानयोग और श्रमण आदि के रूप में आध्यात्मिक साधना की कितनी ही पद्धतियां भारतीय समाज में प्रचलित हैं। व्यक्ति किसी भी पद्धति से योग्य गुरु, आचार्य अथवा स्वाध्यायी परम्परा में अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार साधना कर सकता है।

ऋषि यद्यपि इस संस्कृति वृक्ष का बीज है किंतु संस्कृति के इस ऊर्ध्वमूल वृक्ष का विकास ऋषि दृष्टि प्रसूत वैदिक, औपनि ादिक अथवा पौराणिक काल पर जाकर ठहर नहीं गया है। ऋषि के अनुधावन से गढ़ी गयी परम्परा को आगे बढ़ाने के लिये समय–समय पर बुद्ध, महावीर, नानक, शंकराचार्य, रामानुज–वल्लभ–चैतन्य और आधुनिक काल में विवेकानन्द और अरविन्द तक ने अपना योगदान किया है।

यह महान आध्यात्मिक जीवन शैली जिसमें मनुष्य के प्रत्येक कर्म में धर्म के माध्यम से दिव्यता और शुचिता को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गयी है जिससे मनुष्य एवं समाज सुसंस्कृत बना रहे, स्वतंत्रता के तत्काल बाद शासकीय स्तर पर अलंकृत की जानी चाहिये थी तथा भारत की एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में वैश्विक घोषणा की जानी चाहिये थी। किन्तु अधूरे भारत को मिली अधूरी आजादी के साथ ही अनेक कार्य अधूरे रह गये जिन्हें पूरा करना समय की मांग है।

उपनिषद विद्या–अविद्या के ऋतानुकूल समन्वय का संदेश देते हैं। सारी सृष्टि ही शुभ–अशुभ, जड़–चेतन, क्रोध और करुणा, रति और विरति के रचनात्मक संतुलन पर टिकी है। जब–जब यह संतुलन बिगड़ता है, विकार जन्म लेते हैं। सामंजस्य टूट जाता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय चिंतन में यह स्थिति आकस्मिक है, सनातन नहीं। इतिहास में जब–जब ऐसे काल बिंदु उपस्थित होते हैं, भारतीय मनीषा अपनी आत्मिक–बौद्धिक धरोहर को नये संदर्भों में पुनः परिभाषित, पुनर्व्यवस्थित करती है और भारतीय विद्या का पुनर्जन्म घटित होता है।

बारह सौ वर्षों के सतत संघर्ष से थक कर सोये भारत को एक बार पुनः जगाने की आवश्यकता है। अध्यात्म की आधारशिला पर खड़ा यह राष्ट्र आज भी अविचल है, अजेय है। इस धरती को अपनी मां मानने वाले प्रत्येक भारतीय की आत्मिक शक्ति और अदम्य ऊर्जा को सूत्रबद्ध और संगठित कर सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के जागरण के उद्घोष की प्रतीक्षा विश्व कर रहा है। हम अपने तपोबल और शाश्वत परम्परा के दायित्व का निर्वहन कर समाज की अजेय आकांक्षा एवं अदम्य आत्मविश्वास को पुनर्जागृत कर आध्यात्मिक जगद्गुरु के रूप में राष्ट्र को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये कृतसंकल्प हैं। ■

World Organisation of Students & Youth (WOSY)

Report of International Seminar on

'Global Terrorism'

International seminar on "Global Terrorism" held at Bangalore on 14th and 15th of February 2009 organized by World Organization of Students and Youth (WOSY) was inaugurated on 14th of February 2009 in the Gandhi Krishi Vignana Kendra (GKVK) – University of Agricultural Sciences (UAS), Bangalore. 142 delegates from 31 countries, (which include 30 girls) and 5 continents participated in the seminar.

The seminar was inaugurated by Lt. Gen. S. K. Sinha, former governor of Jammu and Kashmir and Assam. In the Inaugural remarks, Lt. Gen. S. K. Sinha deliberated in detail about the history and evolution, causes and consequences of global terrorism and he gave a call to delegates to keep themselves away from being indoctrinated by religious and ideological preaching of hatred. Ramesh Pappa, international Secretary General, WOSY, gave his introductory remark, wherein he briefed the assembly about the vision and mission of WOSY. He told the delegates that, WOSY believes on a common ,premise of having "Vasudaiva Kutumbakam" meaning world is one family and he emphasized that on this framework WOSY is attempting to offer a platform for the students and youth of the world where they come together, meet each other, express their frank opinion and ideas, exchange thoughts and build consensus on the issues that disturb humanity in total today. He said that only such meetings among youth could result in global peace and civilization harmony. Sri. Sushil Pandit, international Chairman, WOSY, gave an overview of faith terrorism and role of religion in building such terrorism, and how to handle it. He said that the seminar is a beginning to discover an answer to such questions. Latter Dr. Chengappa, VC, University of Agricultural Sciences (UAS), Bangalore, gave is presidential remark, wherein he said terrorism threatens formers, agriculture and food security.

The first session of the seminar was titled " Geo-political framework and role of ideologies in shaping terrorism" and was addressed by Commodore P. K. Viswanathan, VSM, who explained the assembly about state sponsored,

non state sponsored terrorism, kinds of terrorism and its manifestations across the globe. He concluded that no country in the world could be free of terror as some or the other neighbor attacks them with terror.

The second session of the seminar was titled "Arts and Science of Terrorism" wherein Col. T. N. C. Vijayasarathi, VSM, explained the means in which youth are brainwashed and what strategies they use to create a psychological fear amongst the people. He said that only love can handle such issues but not hatred. Later in the evening, there was a cultural event by Kum. Shreya Dinakar, who performed Bharata Natyam, Sri and Smt.. Manjunath Hirematt performed the Magic show followed by a Mongolian dance.

On the second day of the seminar i.e., 15th February 2009, the first session started with an Introduction by Sri. Sushil Pandit on the issues related to role of state, human rights and media in combating terrorism. Later delegate discussed in detail on the aforesaid three issues in separate three groups for about 40 minutes. Leader of each group Habitamv Azezew (Ethopia),Miss Marta (Poland) and Muwafaq (Iraq) summarized the discussion to the assembly followed by remarks by Prof. R. L. M. Patil, chairman of the session. Chairman of the session, Prof. Patil, concluded by stating that state must have greater control over the order of the state. He emphasized the fact that the state must not allow religious and ideological outfits to take control over the order of the state. He also said that media must behave responsible and human right arguments must be fair to all human beings. He echoed the opinion of the discussants and gave a call to the students on developing sensible perception and comprehension in understanding the act of terror. He concluded the session by saying that the terrorism is a new challenge faced by the globalized world and we must discover new solutions to new challenges.

The last technical session was about the role of youth in combating the act of terrorism. During the session, Sri. B. Surendran, joint national organizing secretary, ABVP, gave rational and objective solutions to youth by an open call by

saying that youth must not participate in religious and ideological extremism, youth must develop patriotism towards their respective nations, oppose violence and develop abilities to discriminate the differences between social issues and terrorism.

Later Dr. Nirmala, Mahacharya from Paramahamsa Nityananda Dhyana Peetam gave a call to delegates to quest one's own self, develop peace within oneself wherein a collective conscious of the world could be generated to keep the world in peace. She explained in detail that revolution and revenge cannot eradicate terror. After the session 35 minutes meditation was carried out to pray for global peace.

Discussions were held regarding the silver jubilee conference of WOSY to be held in the year 2010, on the eve of 25th year travel of WOSY as a platform to global youth community. The new Central Council of WOSY with Sh.Dattatrey Hosabale, Prof.Raj Kumar Bhatia,Sh.Sunil Ambekar and Sh.Ramesh Pappa as members of advisory council and Sri. Sushil Pandit, Chairman , Sri. M. S. Chaitra, Secretary General of WOSY along with a total membership of 47 members comprising of 19 countries was also declared on this occassion. At the end of the session delegates expressed their opinion about the seminar and future programmes of WOSY.

On 15th February 2009, the valedictory of the seminar was held in GKVK, UAS Campus,Bangalore. In the session, Sri. Deepak Adhikari, Organizing secretary, Pragnik Vidyarthi Parishad, Nepal gave the report of the international seminar on "global Terrorism". Sri. Sushil Pandit introduced assembly about a very important occasion wherein Sri. Aniketh Kale, General Secretary, Pune chapter WOSY, had marked the history by becoming the first fulltime worker of WOSY. He also appointed Sri. Vinay Chandra as general secretary of WOSY Bangalore Chapter. Sri. Ajith Doval, Former, IB chief, and security advisor, Govt of Karnataka and Sh.Sunil Ambekar, ABVP all India organizing secretary, were the main speakers in the valedictory session.Sri.Ajith Doval delivered his valedictory remarks where he emphasized the fact that one need not be scared of terror because of deaths but because of challenges it offers to humanity. He strongly concluded that the Muslim communities must strongly respond against the radical and Jihadist versions of terrorist outfits. Sri. Sunil Ambekar in his address stated series of examples of people participation in mass to combat terrorism and appealed all the student and youth mass to be united against the ill of terror. Sri. Sunil Pandit concluded the seminar by stating the fact that, the optimism in combating the act of terror comes from gatherings and seminar like the present one wherein youth from different corner of the world gather together with large disagreements, frank opinions and open minds. He said this seminar is a beginning to start our initiative to combating the terrorism.

After the valediction of the seminar, the newly formed International central council had a meeting on taking the decisions on various issues of the future activities of the WOSY, which was attended by 40 members and invitees. It was concluded in the meeting that the next meeting of central council WOSY will meet on 18th and 19th of July in Pune. The probable themes and venues for 2010 silver Jubilee conference of WOSY were discussed in the meeting.

Countries participated in the Seminar

Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Laos, Nepal, Vietnam, Afghanistan, Iran, Iraq, Tajhakisthan, Mauritius, Fiji, Austria, Tibet, Newziland, Uganda, Sudan, India, China, Syria, Ghana, Mongolia, South Korea, Ethiopia, Poland, USA, Kenya, Ivory Coast, Djebuti, Yemen, Uzbekistan. ■

Talibans Withered Garden

– Priyadarsi Dutta –

The lush and fertile Swat Valley in Pakistans North-West Frontier Province has gone under the boots of the Taliban by another name.

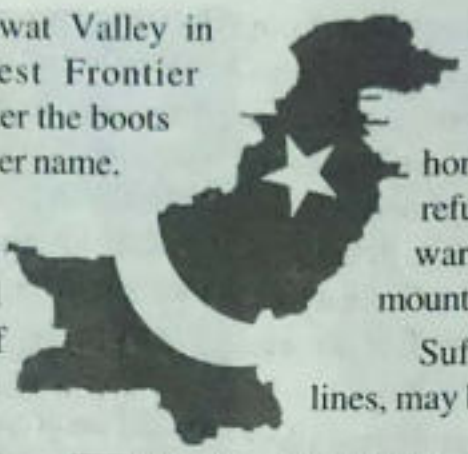

A highly irrigated and fecund valley, it was called *Udyana*, or garden, in ancient India. Second only to far-famed valley of Kashmir, is how Sir Alexander Cunningham describes the region in his book *Ancient Geography of India*. Not unreasonably it is said to be the Switzerland of Pakistan although withered by cross salvos of Islamism in last 15 years.

Tehreek-e-Nifaz-e-Shariat Muhammadi, with whom Islamabad has signed a peace deal, may be leading Zardari, Gilani & Co up the garden path. Its chief, Sufi Mohammed, father-in-law of Mullah Fazlullah alias FM Mullah, has clarified that Islams roadmap doesnt terminate in Swat. He has made no secret of his desire to see Islam rule the world.From the very beginning, I have viewed democracy as a system imposed on us by the infidels. Islam doesnt allow democracy or elections, Sufi Mohammed had said in an interview to DPA a few days before the peace deal was signed. He said the violence could have been avoided had the Government accepted its demand for *shariah* in 1994.

He has precisely articulated the demand of Islamic theologians worldwide vis—vis the infidels. Violence stems not from Islam, they claim, but the perfidious infidels rejecting the invitation of true faith (*Dawat-e-Deen*) and being honoured by Islam. When infidels refuse to embrace Islam voluntarily, warriors of faith are duty bound to mount a violent attack.

Sufi Mohammed, on predictable lines, may be re-reading *Hadith* according to *Shahi Bukhari* Book 50 for Treaty of Hudaibiya. It refers to the Prophets war against Meccan pagans, by breaking a 10-year treaty, which just might provide Sufi Mohammed with a strategy to bring the world under Islam. Meanwhile he might take Swat to Arabian medievalism.

This region Swat and Buner, Dir and Bajur along with Gandhara was where Buddhism flourished second century BC onwards. The invading Greeks, naturalised and nurtured the soulful Buddhist Gandhara style of art. Its fate was sealed when this fortress of Hindu Shahi kings fell to Turks.

Today a more regressive brand of Islam has benighted the light of Asia. William Wordsworth, in Swat, would have repeated what he wrote in another early spring, Have I not reason to lament. What man has made of man?

(Priyadarsi Dutta is associated with India Policy Foundation, New Delhi) ■

मुलाकात

श्री विष्णुदत्त शर्मा

(राष्ट्रीय महामंत्री, अभाविप)

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णु दत्त शर्मा युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भर देने की इच्छा रखते हैं। शिक्षा, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर उनका दृष्टिकोण क्या है? प्रस्तुत है "उमाशंकर मिश्र" द्वारा की गई बातचीत के प्रमख अंश–

हाल ही में अभाविप का 54वां राष्ट्रीय अधिवेशन जलगांव में सम्पन्न हुआ है। किन बातों को लेकर इस अधिवेशन में विचार किया गया?

देश में उत्पन्न हो रहे मौजूदा हालातों और इसके परिणामस्वरूप खडी हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वर्तमान यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण का ग्राफ निरंतर बढ़ा है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मदरसा बोर्ड को सीबीएसई की मान्यता देने की घोषणा की है। सवाल उठता है कि जिन मदरसों को उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते समय-समय पर कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, आज वोट बैंक की राजनीति के चलते यूपीए सरकार ने उन्हें सीबीएसई की मान्यता देने की बात से मदरसों के संदिग्ध गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी चरित्र को जस्टीफाई करने का प्रयास किया है। यह सोचने का विषय है कि कहां सीबीएसई और कहां मदरसा। यही नही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैम्पस अन्य राज्यों में खोले जाने की बात भी कही जा रही है। क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर जेएनयू जैसे संस्थानों का नाम इसके लिए आगे नही आता। अलीगढ़ मुस्लिम विवि. जिस पर पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, इस काम के लिए उसे ही क्यों चुना गया? सरकार तुष्टिकरण के दलदल में आकंठ डूबी हुई है। अभाविप सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना करती है।

इसके अलावा शैक्षिक जगत में पनप रहा भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण मुददा है। देश भर में आयोग्य कुलपतियों की नियुक्तियां हो रही हैं। अन्य नियुक्तियों में भी कुलाधिपति कार्यालयों का हस्तक्षेप बढ़ा है। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई कुलाधिपतियों का हटाया जाना इसी बात का संकेत है। इन सब बातों का सीध प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। तीसरी और हाल ही में पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली बात उदारीकरण के प्रभाव से जुडी है। 1990 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था से देश की जड़ें कमजोर हुई हैं और पाश्चात्य नीति अपनाने से घोटाले भी बढ गए हैं। इन सबके कारण अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ गया है। अभाविप ने इस अधिवेशन में इन तीनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए इस पर देशव्यापी अभियान छेड़ने का निश्चय किया है।

बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में अभाविप के आंदोलन के बारे में बताएं कि इस पर आम जनता एवं सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

देश की सुरक्षा पर बांग्लादेशी घुसपैठ से खतरा बढ़ा है, अभाविप के देशव्यापी आंदोलन से यह बात लोगों को समझ में आई है और समाज में इस समस्या खिलाफ एक वातावरण बना है। जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आम जनता में भी चर्चा आरंभ हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका हाल की आतंकी घटनाओं में भी रही है। आंदोलन से सरकार पर दबाव बना है। तुष्टिकरण का राग अलापने वाली सरकार को अभाविप के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है और यही कारण है कि इस समस्या को देश के गृहमंत्री को भी स्वीकार करना पड़ा। अभाविप की चिकननेक सीमा पर रैली के पश्चात् वहां सीमा को दुरूस्त करने का काम आरंभ हो रहा है। घुसपैठ को लेकर संसद में सवाल

उठ रहे हैं और केन्द्रीय नेतृत्व एक छात्र संगठन के इस अभियान से सकते में आ गया है। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है कि–'घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाना होगा।'

कर्नाटक में पब बंद किए जाने की मांग उठाई जा रही है, इस कदम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

पब कल्चर और वेलेन्टाईन्स–डे पश्चिम की देन हैं और भारत में इसके प्रसार के पीछे युवाओं को दिग्भ्रमित कर उन्हें अपने सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश से दूर करना और बाजार की फांस में जकड़कर अपना उल्लू सीधा करना है। इस बाजारवादी रवैये के खिलाफ है जो भारतीयों को अपनी जड़ों से काटने पर तुला हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभाविप युवाओं में जागरूकता का प्रसार अनुशासन के साथ करना चाहती है। अपने रचनात्मक कार्यक्रमों से हमने समय–समय पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। Save Campus और Safe Culture जैसे अभियान इस बात के गवाह रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम तो अभाविप की कार्यप्रणाली में दिन–प्रतिदिन का हिस्सा हैं।

मध्यप्रदेश सरकार शैक्षिक पाठ्यक्रमों में 'राष्ट्रवाद' जैसे विषय को शामिल करने जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

तुष्टिकरण और शिक्षा व्यवस्था पर वामपंथी आक्रमण के दौर में छात्रों को अपने देश की गौरवशाली परंपराओं एवं राष्ट्रीय मूल्यों से परिचित कराना निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। शैक्षिक परिवेश में राष्ट्रीयता एवं भारतीयता का भाव होना चाहिए। आज मूल्यपरक शिक्षा की जरूरत है और इस तरह के पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू किए जाने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की राजनीति के चलते यूपीए सरकार ने एनसीईआरटी की 175 पुस्तकों में इस देश की महत्वपूर्ण परंपराओं, चिंतन एवं उपलब्धियों से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ कर भावी पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यह एक तरह से देश के स्वाभिमान और राष्ट्रीयता पर आक्रमणा था, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को इन विवादास्पद तथ्यों को पुस्तकों से हटाना पड़ गया। वास्तव में आज शिक्षा के भारतीयकरण की नितांत आवश्यकता है।

लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। अभाविप की इस चुनाव में राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षाएं हैं?

राजनीतिक दलों से हम मांग करते हैं कि वे शिक्षा, सुरक्षा एवं रोजगार से जुड़े विषयों पर अपना एक व्यापक दृष्टिकोण घोषणा पत्र में उजागर करें। जनता के सामने एक प्रभावशाली मॉडल रखने की आवश्यकता है। जिस तरह से यूपीए सरकार ने शिक्षा एवं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, देश के युवाओं में इस बात को लेकर जागृति आई है। क्या इस तरह के लोगों को राज सौंपना चाहिए? इस बात पर देश के युवाओं को भी विचार करना चाहिए।

अभाविप की स्थापना के 60 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर संगठन की नवीनतम योजनाएं क्या है?

इस अवसर पर हमने देश की सुरक्षा एवं संगठन के सुदृढ़ीकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए दृढ़ निश्चय किया है। देश की सुरक्षा पर खतरा बन चुके पाकिस्तान को आतंकवादी देश और बांग्लादेश को शत्रु देश घोषित करने की मांग हम सरकार से करेंगे। यही नहीं पाक अधिकृत कश्मीर और बांग्लादेश में चल रहे आतंकी शिविरों को सैन्य कार्यवाही कर नष्ट करने की मांग भी अभाविप जोर–शोर से उठाएगी। सीमा पर घुसपैठ रूके, सीमा प्रबंधन दुरूस्त हो इसके लिए भी सरकार पर दबाव निरंतर बनाया जाता रहेगा, जब तक कि समस्या का अंत नहीं हो जाता।

60 साल पूरे होने पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाना और देश के प्रबुद्ध वर्ग, छात्रों एवं युवाओं को इसमें शामिल करना हमारा लक्ष्य होगा। यही नहीं गत वर्ष हमने देश भर में 16 लाख छात्रों की सदस्यता की थी, जबकि इस बार हम 25 लाख छात्रों को अभाविप का सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा इस बार संगठनात्मक विस्तार के स्तर पर अभाविप के कार्य को +2 के छात्रों तक विस्तृत करने की योजना है।

शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ सरकार डटकर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है?

शिक्षा के बाजारीकरण से प्रतिभावान गरीब छात्र उच्च शिक्षा से दूर होता जा रहा है। अभाविप ने इस बात को लेकर समय–समय पर आंदोलन खड़े किए हैं और इस बार हम एक देशव्यापी विशाल आंदोलन शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ खड़ा करने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार ने इस मामले पर हमेशा ढुल–मुल रवैया अपनाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् काफी समय से इस बाबत एक केन्द्रीय कानून बनाने की मांग सरकार से करती रही है। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मानव संसाधन विकास

मंत्री अर्जुन सिंह ने भी शिक्षा का व्यावसायीकरण रोकने के लिए केन्द्रीय कानून के मसौदे पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन अभी तक इस पर कोई कारगर कदम इस पर नहीं उठाया गया है। हालांकि मध्यप्रदेश ने इसी तरह का राज्य स्तरीय कानून बनाकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। व्यावसायिक, मेडिकल एवं डेंटल शिक्षा के मनमाने व्यापार पर इससे लगाम लगाया जा सकेगा। इस तरह का कानून पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बनना चाहिए। अभाविप सर्वेक्षण कर रही है कि देश भर के कितने व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों में कितनी फीस वृद्धि हुई है। छात्रों से शिक्षा के नाम पर जो लूट हो रही इसे रोकने के लिए प्रभावी कानून बनना चाहिए। बड़े–बड़े कार्पोरेट और उद्योगपति भी आज शिक्षा के माध्यम से व्यापार करने लगे हैं। इस तरह से तो देश भर में दो वर्गों को उदया होने लगेगा; एक पैसे वाला और दूसरा गरीब प्रतिभावान छात्र। देश में विषमता की खाई ऐसे में बढ़ेगी। शिक्षा तो सेवा का विषय है, जबकि विडंबना है कि यह आज व्यापार और बाजार का केन्द्र बन चुकी है।

गौर करने वाली बात है कि किसानों की आत्महत्या के मूल में लोन की महती भूमिका रही है। हमने अपनी कृषि नीति में सुधार करने की बजाय लोन देकर किसानों के हालात सुधारने का ढिंढोरा पीटा, इसके परिणामस्वरूप हजारों किसान आत्महत्या को विवश हो गए। आज इसी तरह की अदूरदर्शिता की नीति शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनाई जा रही है। एक तरफ तो शिक्षा महंगी हो रही और दूसरी तरफ लोन देकर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। क्या ऐसे में हम छात्रों को आत्महत्या की ओर नहीं धकेल रहे हैं? इस बात पर भी विचार करना होगा।

शिक्षा के अतिरिक्त किस प्रकार के रचनात्मक कार्य विद्यार्थी परिषद् करती है?

अभाविप, हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर काम करती है। सामाजिक विषयों में विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभावग्रस्त इलाकों में जाकर काम करना भी इसमें शामिल है। पानी को गांव में कैसे रोका जा सकता और ग्राम विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर 'श्रमानुभव शिविर' एवं 'गांव दर्शन' जैसे कार्यक्रम इसके निमित्त चलाए जाते हैं। पूरे देश में देशभक्ति के प्रति एक राष्ट्रभाव जागृत करने और अपने देश के प्रति स्वाभिमान लोगों में जागृत हो इसके लिए भी जनजागरण अभियान चलाए जाते हैं। ■

PIL Against Scholarships For Religious Minorities

A PIL has been filed in the Bombay High Court against a scholarship scheme for religious minorities. The scheme, launched by the Union Ministry of Minority Affairs last year, provides for 20,000 scholarships on merit and income basis for students from Muslim, Sikh, Christian and Parsi communities.

Petitioner Sanjeev Punalekar, a city-based advocate, has taken exception to it saying that "it excludes Hindus and Jains, who constitute eighty per cent of the population". Such "discrimination" on the basis of religion is against the constitutional principle of equality, the petition said.

Further, it violates the Hindus' and the Jains' freedom to practice their respective religions, as the sops to other religionists "makes them (the Hindus and the Jains) more vulnerable to the allurement" and leads to conversions, the PIL alleges.

Last week, a Division Bench of Justices JN Patel and VK Tahilramani posted the petition after four weeks for hearing, asking the Centre to file its reply.

शिक्षा एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण - विद्यार्थियों की भूमिका

राज्य स्तरीय विद्यार्थी संगोष्ठी

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा शिक्षा एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर एक राज्य स्तरीय विद्यार्थीयों की संगोष्ठी का दो दिवसीय आयोजन दि. 9 व 10 फरवरी को प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक न्यू कान्फ्रेंस हॉल, उत्तरी परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व के समग्र विकास एवं राष्ट्र के नागरिक तैयार करने में किसी भी देश में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम–पाठ्यचर्या, गुणात्मकता, सुलभता तथा देश की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा आदि विषयों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही है। विद्यार्थी शिक्षा जगत का सबसे बड़ा घटक होने के बावजूद शिक्षा के विभिन्न आयामों पर हो रही बहस से इन्हे दूर ही रखा गया है। इस हेतु शिक्षा एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण में छात्रों की भूमिका पर दो दिवसीय परिसंवाद का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। यह परिसंवाद विद्यार्थियों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एवं विद्यार्थियों का है। विभिन्न सत्रों में लेख प्रस्तुत करने हेतु केवल छात्रों को ही आमंत्रित किया जा रहा है। यह संगोष्ठी शिक्षा क्षेत्रों में छात्रों की पहल को मजबूत करने का एक विनम्र प्रयास है। इस परिसंवाद का उद्घाटन डा. जी. एस. सक्सेना, पूर्व कुलपति आगरा विश्वविद्यालय ने किया।

उन्होने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा कि अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता, राष्ट्र पुननिर्माण की कुंजी है। – राष्ट्र के पुननिर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के अधिकतर साहित्य जिससे हमे शिक्षा मिलती है। ऋग्वेद जो कि संस्कृत भाषा में है आज उस संस्कृत को मृतभाषा बना दिया गया है।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सह–सचिव श्री अतुल कोठारी ने बताया कि शिक्षा बचाओ आन्दोलन शिक्षा में विकृतियों के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है। शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति ने शिक्षा में एक नया विकल्प देने का प्रयास कर रहा है। समापन में डा. बी. एस. राजपूत, पूर्व कुलपति कुमांयू विश्वविद्यालय, नैनिताल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री दीनानाथ बत्रा जी ने विद्यार्थीयों से आह्वान किया कि राष्ट्रपुनर्निर्माण के इस पवित्र कार्य में अपना सक्रिय योगदान करे। सकारात्मक सोच, सृजनात्मक सहयोग तथा सेवा कार्य से वह विश्वविद्यालय के स्वरूप को बदल सकते है।

इस परिसंवाद में उद्घाटन, समापन को छोडकर सात सत्र रहे। जिसमें लगभग 24 से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया तथा अपने लेख पढ़े। परिसंवाद में लगभग 200 छात्र सहभागी रहे।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की शुरूआत भारतीय संस्कृति एवं जीवनादर्शों के अनुरूप शिक्षा विकसित करना जिससे अनुप्राणित होकर शिक्षा के लिये समर्पित कार्यकर्ता राष्ट्र के पुनर्निर्माण के पावन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विश्वासपूर्वक बढ़ सकें। आधुनिकतम ज्ञान, विज्ञान तथा प्राचीन उपलब्धियों का पूर्ण उपयोग करते हुए ऐसी शिक्षण प्रणाली एव संसाधनों को विकसित करना है जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास के शैक्षिक उदे यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति सुलभ हो सके। ■

क्या प्रमाणित तौर पर स्लमडोग है भारत ??

निशा डुडेजा

भारत का ऑस्कर मिला है यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। जिसे पाने के लिए हम बरसों से कोशिश कर रहे थे, और आज वह इतनी कोशिशों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। जो लोग यह सोचते हैं कि यह भारत के लिए सम्मान न होके अपमान है तो मैं यही कहुंगी कि कहीं न कहीं हम लोग सच्चाई से भाग रहे हैं। भारत में जो है वही इस फिल्म में दिखाया गया है और सच के बल पर हमें जो पुरस्कार मिला है उस पर हमें खुश होना चाहिए। लोग जिन स्लम एरिया के नाम से भी घिन करते थे आज वही सुबह से शाम तक न जाने इसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सच्चाई को सामने लाकर ही उसमें छुपी बुराईयों को दूर किया जा सकता है। यानि स्लम के जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना करने के बाद ही अब स्लम के जीवन को लोग समझ पाएंगे और उस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा तो जरूर ही होगा।

कविता

स्लमडॉग को ऑस्कर मिला है यह बात मुझे बहुत खुशी देता है। बात इसकी नहीं कि भारत पर बनी फिल्म को यह अवार्ड मिला है बात उन लोगों की भी है जिन्होंने इस सच्चाई को इतने अच्छे तरीके से कैद किया और उसे एक फिल्म के रूप में पेश किया। देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा है। आज भी हम भारतीय कहीं न कहीं इस सच्चाई से दूर ही थे कि हम इतनी गरीबी वाले देश का हिस्सा हैं जिसे गरीब होने के कारण अवार्ड तक मिल गया। कम से कम अब वो मेहनत करेंगे और अपने देश को उस पैबंद से मुक्त कराएंगे।

उपमा

मुझे लगता है स्लमडॉग फिल्म जो कि भारत की गरीबी पर फिल्माई गई है वह सरासर भारत का अपमान है। हमारा देश हमारा अपना है, जिस तरह हम अपने घर में रूखी–सूखी खाकर भी खुश होते हैं और दूसरों को यह कानों कान खबर भी नहीं होने देते कि हमने क्या खाया है। ताकि कोई हमारा मजाक न बनाए उसी तरह यह देश भी हमारा घर है , जैसा भी है हम इसमें खुश है और विकसित होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं , इसके लिए हम अपने देश की इस लाचारी को प्रसारित कैसे कर सकते हैं। विदेशो की नजर में भारत शुरू से ही गरीब और लाचार देशो की गिनती में नम्बर 1 पर गिना जाता है जिसे ऑस्कर के रूप में एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है।

गुड़िया

हाँ यह बात बिल्कुल सच है कि अब हम घोषित तौर पर स्लमडॉग हो चुके हैं। आज जिस तरह से पूरे विश्व में भारत की गरीबी का प्रचार–प्रसार हुआ है। उसे देखकर तो यही लग रहा है। यह ऑस्कर भारत पर बनी उस फिल्म को बिना है जिसमें भारत की सच्चाई को नंगा किया गया है इसलिए यह हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। यह गर्व तब होता जब भारत अपनी किसी उपलब्धि के लिए यह अवार्ड प्राप्त करता। इस फिल्म ने न जाने कितने शोधकर्ताओं को भारत की गरीबी पर अच्छा खास रिसर्च मैटर उपलब्ध करा दिया है। इसलिए बजाए खुश होने के यदि हम यह सोचे कि हमें भारत पर लगे इस धब्बे को अपने किसी अच्छी कारनामें से धोना होगा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ■

Acharya Jagadish Chandra Bose

Born: November 30, 1858

Achievements: He was the first to prove that plants and metals too have feelings. He invented wireless telegraphy a year before Marconi patented his invention.

Jagdish Chandra Bose was born on November 30, 1858 in Mymensingh (now in Bangladesh). His father Bhagabanchandra Bose was a Deputy Magistrate. Jagadish Chandra Bose had his early education in village school in Bengal medium. In 1869, Jagadish Chandra Bose was sent to Calcutta to learn English and was educated at St.Xavier's School and College. He was a brilliant student. He passed the B.A. in physical sciences in 1879.

In 1880, Jagdishchandra Bose went to England. He studied medicine at London University, England, for a year but gave it up because of his own ill health. Within a year he moved to Cambridge to take up a scholarship to study Natural Science at Christ's College Cambridge. In 1885, he returned from abroad with a B.Sc. degree and Natural Science Tripos

After his return J.C.Bose, was offered lectureship at Presidency College, Calcutta on a salary half that of his English colleagues. He accepted the job but refused to draw his salary in protest. After three years the college ultimately conceded his demand and Jagdish Chandra Bose was paid full salary from the date he joined the college. As a teacher Jagdish Chandra Bose was very popular and engaged the interest of his students by making extensive use of scientific demonstrations. Many of his students at the Presidency College were destined to become famous in their own right. These included Satyendra Nath Bose and Meghnad Saha.

In 1894, Jagadish Chandra Bose decided to devote himself to pure research. He converted a small enclosure adjoining a bathroom in the Presidency College into a laboratory. He carried out experiments involving refraction, diffraction and polarization. It would not be wrong to call him as the inventor of wireless telegraphy. In 1895, a year before Guglielmo Marconi patented this invention, he had demonstrated its functioning in public.

Jagdish Chandra Bose later switched from physics to the study of metals and then plants. He fabricated a highly sensitive "coherer", the device that detects radio waves. He found that the sensitivity of the coherer decreased when it was used continuously for a long period and it regained its sensitivity when he gave the device some rest. He thus concluded that metals have feelings and memory.

Jagdish Chandra Bose showed experimentally plants too have life. He invented an instrument to record the pulse of plants and connected it to a plant. Although Jagdish Chandra Bose did invaluable work in Science, his work was recognized in the country only when the Western world recognized its importance. He founded the Bose Institute at Calcutta, devoted mainly to the study of plants. Today, the Institute carries research on other fields too.

Jagdish Chandra Bose died on November 23, 1937. ■

आपदा प्रबंधन में बनाए अपना भविष्य

– प्रीति पाण्डेय –

हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं पर किसी का ज़ोर नहीं है। सूखा, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी फटने और भयंकर बारिश आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। इनकी चपेट में आने से बचने के लिए न तो पहले से कोई तैयार की जा सकती है और न ही इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक कम जरूरी किया जा सकता है। ताकि कम से कम नुकसान हो। चूंकि एक प्राकृतिक घटना न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। इससे जान का नुकसान तो होता ही है साथ ही देश को आर्थिक हानि भी होती है।

हममें से प्रत्येक व्यक्ति दिन–प्रतिदिन अपने–अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में जनसेवा का भाव है तो वह अपना कैरियर आपदा प्रबंधक के रूप में सैटल कर सकता है।

क्या है आपदा प्रबंधन?

आपदा प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन हैं जिसमें भविष्य में होने वाले खतरों की पहचान की जाती है और कोशिश की जाती है कि पहले से ही उन खतरों का और उनसे होने वाले प्रभावों का कम से कम असर हो।

जिस क्षेत्र में खतरे होने का अनुमान हो वहां संबंधित सूचना जारी करवाना तथा तमाम आकड़ें प्रदान करना भी आपदा प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत ही आता है। आपदाओं का सामना करने और उनसे होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कहां और क्या–क्या व्यवस्थाएं की जानी है तथा इन व्यवस्थाओं पर कितना निवेश करना है यह सब यही विभाग देखता है। यह कार्य अनुमान के आधार पर ही किए जाते हैं। चूंकि यह पहले से ही आपदा के पूर्वानुमान के आकलन का प्रयास करते हैं और आवश्यक एहतियात बरतते हैं।

जनशक्ति, वित और अन्य आधारभूत समर्थन आपदा प्रबंधन की उप–शाखा का ही हिस्सा हैं। आपदा के बाद की स्थिति आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण आधार है। जब आपदा के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है तब लोगों को स्वयं ही उजड़े जीवन को पुनः बसाना होता है तथा अपने दिन–प्रतिदिन के कार्य पुनः शुरू करने पड़ते हैं।

आपदा प्रबंधक के कार्य

आपदा प्रबंधकों को ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने का कार्य करना पड़ता है। आपदा प्रबंधक व्यावसायिक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समस्त आवश्यक सहायक साधन और सुविधाएं सही समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध हों, जिससे कम से कम नुकसान होता है।

यह प्रबंधक ऐसे विशेषज्ञ लोगों के समूह का मुखिया होता है, जिनकी सेवाएं आपदा के समय अनिवार्य होती है। जैसे–डॉक्टर, नर्स, सिविल इंजीनियर, दूरसंचार विशेषज्ञ, वास्तुशिल्प, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि।

आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती आपदाग्रस्त सीमा–क्षेत्र और होने वाली क्षति का आंकलन करना है। इससे इस क्षेत्र का कार्य अत्यधिक वैज्ञानिक प्रक्रिया का रूप ले लेता है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों की भौगोलिक एंव आर्थिक स्थितियों के कारण चुनौती और भी बढ़ जाती है।

आपदा अधिकार – क्षेत्र की तमाम सीमाएं लांघ सकती है। विपत्ति के समय अनजान कार्यो की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष कर्मियों की जरूरत होती है। इससे यह कार्य और अधिक सरल हो जाता है। आपदा प्रबंधक को कभी भी आपदा के समय यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा काम उसका है और कौन सा नहीं आपदा को कंट्रोल में लेने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जिस क्षेत्र में आपदा आई है वहां के लोगों को उससे कम से कम हानि हो और वहां के क्षेत्र में कम से कम असुविधा हो इस बात की जिम्मेदारी एक आपदा प्रबंधक की ही होती है।

योग्यताएं:–

इस पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी के पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। कुछ संस्थानों में स्नातक होना जरूरी

है। और इसके साथ ही जन सेवा की भावना का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए इस क्षेत्र में कार्य के दौरान या इस क्षेत्र में कार्यरत अनेक संगठनों के साथ स्वयंसेवा से ही आप इस पाठ्क्रम का व्यवहारिक रूप देख सकते हैं ताकि किताबी ज्ञान के साथ–साथ आपको व्यवहारिक तौर पर भी कुछ सीखने को मिले।

संस्थान:

Indian Institute of Ecology and Environment
www.technologyindia.com
Indira Gandhi National open University
www.ignou.ac.in
Gujarat Institute of Disaster Management
www.gsdma.org
Disaster Management Institute, Bhopa
www.dmibpl.org

रोजगार के अवसर :

आपदा प्रबंधन का कोर्स करके आप सरकारी आपदा प्रबंधन कार्यालय में नौकरी हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा आप इसी क्षेत्र में कार्यरत किसी एन.जी.ओ के साथ जुड़ कर अपनी सेवाएं दे सकते हैं.

वेतन :

केंद्रिय सरकार के वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है। बाकी आप किसी एनजीओ के साथ समय–समय पर अपनी सेवाएं देकर भी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

(साभार : सहारा) ■

Right to Education More Rhetoric Than Action

– By Girish Awasthi –

On this 60th Republic Day the Indian polity should resolve to address the ill-wills of Indian educational system and address it with a right perspective. At present we are insisting open secular education, which is harmful to our society. More than 70 per cent of the population of our country belong to the rural areas. It is therefore necessary to search intellectuals from the rural areas in comparison to urban areas.

Government's policy for establishment of universities and technical institutes is oriented towards acquiring a formal university degree and not necessarily acquiring skills for greater employability. Consequently, those educated but without professional skills constituted 69 per cent of the total unemployed and a meagre 13 per cent of these university graduates are employable. A surprising fact that the higher educational institutes currently functioning or controlled by private persons are the off-shoots of political persons intended to mint money through those institutions.

On this 60th Republic Day, I consider the education as one of the important aspects confronting Indian polity. Literacy and education are the most effective parameters to measure the human development index for a nation. Ever since the Independence, these issues have been discussed and leaders have also raised concern with amplified note. Around 45 per cent to 50 per cent of our population would be below the age of 25 by 2015. As against the present increased enrolment at

primary level due to Sarva Shiksha Abhiyan initiated by NDA Government, the drop out rate of school children before completing Grade VIII is around 53 per cent. The quality of education is another major source of anxiety for the nation, in terms of infrastructure; thousands of schools are lacking in basic facilities like classrooms, blackboards, teachers, toilets, electricity and drinking water facilities etc.

The Government has now proposed the Right to Education a statutory back-up to provide education a Fundamental Right for all children aged 6-14. We can definitely say that the education and health sectors are victims of political and bureaucratic neglect and maladministration. Secondary and higher education are important terminal stages in the system of general education, but the present system of education since 9th Standard to 12th Standard do not have a vocational bias to link it with the world of employment.

Even highly qualified individuals are searching for right employment and end up with a job which is irrelevant to the field of their study at higher education level. Partly responsible for this Indian mind-set and the government's policy for establishment of universities and technical institutes are oriented towards acquiring a formal university degree and not necessarily acquiring skills for greater employability. Consequently, those educated but without professional skills constituted 69 per cent of the total unemployed and a meagre 13 per cent of these university graduates are employable. A surprising fact that the higher educational institutes currently functioning or controlled by private persons are the off-shoots of political persons intended to mint money through those institutions. Dr C Rangarajan, the noted economist, former RBI Governor and the Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister has been stressing upon identifying gaps in the supply of labour and provide training to make available the skills that are in short supply. He underlined that we need more technicians than engineers, more para medical staff than doctors. The country's educational system has to focus on vocational training on producing quality professionals.

At this hour of crisis, I remember my mentor the late Dattopant Thengadi, who much before the famous Management Guru Peter F. Drucker in late 60's, said that the future India would not have the struggle between economic haves and have-nots, but between educational haves and have-nots. In 1990 Drucker said in finely tuned words that after the fall of communism and in the age of globalised economy the true fight would be between knowledge workers and service workers. In contrary to the slogans of sectarian thinkers Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) says that it is production by masses that matters and not mass production, and similarly it is consumption by masses and not mass consumption (by a few).

The vital symptoms of our labour markets are horrible. Unemployment may reach 29 per cent by 2020. Our demographic dividend means 7.4 crore people (25 per cent of world's new workers) need jobs till 2010. As per Economic Survey 2007-08, 68.4 per cent India's population would be in the working age of 15 to 64 years in 2006, a rising of 62.9 per cent from 2006. A Survey says that 80 million new jobs could be created in the next 10 yeas across India, of which 75 per cent will require vocational skills. Another study indicates that is an estimated 46 million-workforce deficit by 2020 while India would have an estimated surplus manpower of 47 million. We have got an opportunity which needs to be converted to our advantage by giving education and skill development the due importance in the planning process.

Despite the recommendations of DC Kothari Commission and the National Educational Policy 1968, that we could not make it possible to deliver at least 50 per cent of the students completing Class X to the vocational stream. Another centrally sponsored scheme launched in February 1988, the vocationalisation of Secondary Education, did not yielded results due to poor allocation and lack of interest with political and executive administration. Attention has to be paid to these 21 million-target group. As against this, available formal training capacity of the country is only 2.3 million students, which leaves a gap of 18.7 million. Besides ITI system, we need to revamp the entire educational system to fill up this gap. Besides, we need to take an urgent need to cater to the Class-VIII pass-outs, whose numbers will swell with the success of the Universaliation of Elementary and Middle Education and Sarva Shiksha Abhiyan initiatives. The vocational education scheme should focus on the capacity of local industry to absorb students of a particular trade.

From the employment point of view, it is always considered that the educational planning in India from upper primary level is targeted to the needs of affluent urban population of India. From the period of great sage Adi Shankara to Mathematician Ramanujan and Sir CV Raman, they had education with right intent from rural/ semi-rural hub and not in the institutions existing in mega cities which teach the children to ask for money instead of making them earn money.

On this 60th Republic Day the Indian polity should resolve to address the ill-wills of Indian educational system and address it with a right perspective. At present we are insisting upon secular education, which is harmful our society. More than 70 per cent of the population of the country belong to the rural areas. It is therefore necessary to search intellectuals from the rural areas in comparison to urban areas. An earnest action on following suggestions would make us look at the educational aspect in right perspective:

1. Instead of merely enacting the "Right to Education Bill", the Government should think of Right to Education, which may provide a reasonable employment. It would also address to the demand for enacting a bill for Right to employment.
2. The school education should be made free at least up to secondary level. Focus should be given to enhance the quality of education by the public authorities.
3. To give more impetus to skill development, it should be declared as a national priority. The vocational training under Ministry of Labour is transferred to Ministry of HRD and they are mandated to provide holistic education aimed at employment and emancipation. The expenditure on education should be doubled from the present 4 per cent of GDP.
4. Continuous enhancement of skills should be made compulsory for employers and employers / industry should be made to contribute at least a 2 per cent of their profit.
5. Soft skills course should be mandatory for all undergraduate and postgraduate students, as like the one initiated by Madras University in Tamil Nadu.
6. Pre-vocational education provided from Class IX and X under the National Policy of Education 1986 should now be universalised and at least 50 per cent of educational institutions in the country are changed to the new-syllabi aimed at providing skills to young hands. ■

Karnataka

ABVP Seeks Probe Into Revaluation Of Answer Scripts

Bangalore: Karnataka unit of the ABVP alleged large-scale irregularities in the revaluation of answer scripts of 3,582 of II and III year engineering students of the Visvesvaraya Technological University, Begalum, and sought a departmental probe into the issue.

Speaking presspersons at the Bangalore Press Club , Secretary P.M. Ravichandra charged that many students stand would lose their eligibility to appear to the final year of BE due to the negligence by the university authorities.

Many students had virtually contested the revaluation in individual subjects had seen no change in their marks when the results were announced last week. The Minister for Higher Education Aravind Limbavali has been informed on the issue and urged him to order the departmental inquiry, he said.

The VTU had published of III, IV, V and VI semester results but did not give details except whether the student has passed or failed. The students' eligibility for the final year examination is at stake due to negligent evaluation. The syllabus had changed and it was impossible for students to appear for exams in new subjects and to waste one more year for study, a press note said.

ABVP Protests Pub Culture

MYSORE: Though the ABVP has condemned the act of Sri Sena, attacking girls in Mangalore pub, it has also slammed pub culture.

The ABVP has called for a campaign against Western culture, female foeticide, consumption of alcohol and women dancing. Observing that the pub culture is a serious blow to Indian culture and morality, it has asked girls and women to contribute in nation-building instead.

The ABVP has decided to launch an agitation against pub culture. It has asked the government to take stringent action against those taking law into their hands. ABVP organised a two-day rally at Sri Adi Chunchanagiri community hall in Shimoga on February 7, and discussed the problems faced by the girls in women's hostels.

Jharkhand

ABVP to Step Up Agitation

Dumka: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), has threatened to step up their agitation and paralyse Sidho-Kanhu Murmu University (SKMU) for its alleged apathetic attitude towards the problems of the students.The student representatives were furious after SKMU vice-chancellor Victor Tigga refused to hold a discussion on the issues raised by the students.

They staged a dharna in front of the venue for the meeting of — SP College auditorium. The meeting has been postponed due to the agitation.

The demands of the students were betterment of facilities at the university headquarters, regularisation of academic sessions, hike in prices of examination forms and other fees. To these the university expressed its helplessness on one pretext or the other. ABVP, has alleged that the administration has been neglecting their problems citing financial crunch.

Madhya Bharat

ABVP Protest Against Department Decision

Bhopal: The ABVP has criticised the Department of Higher Education's recent decision,

in which the commissioner had made it compulsory for the students to open their bank account with a particular bank. ABVP State secretary Hitesh Shukla has informed that the decision makes it compulsory for students to open accounts with State Bank of India, which requires minimum balance of Rs 1,000. He has alleged that this amount is not affordable for the poor beneficiaries of the scholarship schemes. He has demanded that the arbitrary attitude of the commissioner should be controlled soon. Shukla has demanded that either the compulsion of opening account with SBI should be withdrawn or the minimum balance amount should be lowered for students.

Bihar

ABVP Protest against Bangladeshi Infiltrators

Patna: ABVP staged a demonstration to protest against steady influx of illegal immigrants from Bangladesh who were causing all sorts of problems including contributing to terrorism in the nation.The rally began at the Gandhi Maidan and after passing through Frazer Road and Dak Bungalow crossing, arrived at the Income Tax roundabout where they staged a dharna demanding tougher border policies and deportation of illegal aliens.

Later, a group of protestors met with Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi and handed over a memo to him to press for their demands.

ABVP National Secretary Ramashankar Sinha said India was facing an unprecedented illegal alien problem under the Congress-led UPA government that has not only failed to check their inflow; it was in fact encouraging them to come to India in an attempt to strengthen their base with the Muslim voters.

"Today, India is more in danger of foreign threat than ever before because of the large number of illegal nationals entering into our country with the sole purpose of wreaking political havoc in the nation. If our government does not wake up soon, we will end up paying heavy price for our freedom," Sinha said

Uttar Pradesh

ABVP Protest Against Unauthorised Entry of Bangladeshis

Allahabad: The activists of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) protested against the intrusion of Bangladeshi people into the country and shouted slogans against the governments apathy to this problem. They later handed over a memorandum to ADM (City) addressed to the president of India.

Addressing the public gathering, Subhash Singh, NEC member of ABVP said, "The unauthorised entry of Bangladeshi people is threat to the sovereignty of the country and we would not tolerate this kind of intrusion."

He said that it was imperative that the administration should go into the root cause of the entry of Bangladeshi into the Indian soil and efforts should be made to stop these illegal entries.

Gyan Prakash Shukla, city secretary of the Parishad said that the members of the party organised a massive meeting at Kishanganj to wake this government about the gravity of the problem. Only then the government would wake up from its slumber and realise that unauthorised entry of Bangladeshi people was taking place in the country. He warned that if the government failed to take proper steps to check Bangladeshi infiltration into the country, then people would be forced to intensify struggle.

WOSY International Seminar on Global Terrorism

Shri S K Sinha Inaugurating the Seminar

Delegates from Different Countries

Valedictory Function

Meditation Session

Office Bearers of WOSY Central Council

Warriors who lead this great movement ahead for the last 60 years